खनन विभाग बना मॉडल डिपार्टमेंट

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के अधिकारी उत्तराखंड पहुंचे

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (14 Oct.): सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के कई विभागों द्वारा जनहित व राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है. जिनमें खासकर खनन विभाग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. कहा, राज्य के खनन राजस्व में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने नई खनन नीति प्रभावी, पारदर्शी व सशक्त रूप से लागू की है. सीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही व सख्त निगरानी व्यवस्था के कारण कहीं भी लीकेज या अनियमितता की कोई संभावना नहीं रह गई है.

दूसरे राज्य कर रहे स्टडी

सीएम ने कहा कि राज्य की यह नीति व कार्यप्रणाली अब अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन चुकी है. इस वजह से हिमाचल व जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के प्रतिनिधि अधिकारी भी उत्तराखंड पहुंचकर खनन क्षेत्र में लागू क्रियान्वित मॉडल की स्टडी कर रहे हैं. उत्तराखंड की नीतियों व व्यवस्थाओं को अपने स्टेट्स में लागू करने के प्रयास कर रहे हैं.

6 लाख श्रमिक बोर्ड में हों रजिस्टर्ड

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी मनरेगा श्रमिकों को शीघ्रतापूर्वक भवन व सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत कवर किया जाए. ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर हो. निर्देश दिए कि अगले 3 माह में कम से कम 5 से 6 लाख श्रमिकों को बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड किया जाए. कहा, श्रम विभाग व बोर्ड के अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे हर श्रमिक तक पहुंच बनाएं. उन्हें कल्याणकारी योजनाओं व सुविधाओं की जानकारी दें. सीएम की अध्यक्षता में भवन व सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक हुई. इस दौरान सीएम ने बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों व उनके आश्रितों के कल्याणार्थ ऑनलाइन पोर्टल व डीबीटी से करीब 10 हजार श्रमिकों व उनके परिजनों को 11.50 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित की.

एक नजर

- श्रमवीरों के कल्याण के लिए 11.50 करोड़ की आर्थिक सहायता डीबीटी से ट्रांसफर
- सीएम की अध्यक्षता में उत्तराखंड भवन व सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक
- सीएम बोले- श्रमिकों के सम्मान व कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
- श्रम विभाग व बोर्ड के अधिकारियों का दायित्व, हर श्रमिक तक बनाएं पहुंच
- सीएम के निर्देश, अगले 3 माह में कम 5 से 6 लाख श्रमिकों को बोर्ड के

> राज्य का विकास हमारे श्रमिक भाइयों-बहनों के परिश्रम पर आधारित है. उनके कल्याण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. सभी मनरेगा श्रमिकों को कल्याण बोर्ड के तहत लाना हमारा लक्ष्य ही नहीं, यह सरकार की जिम्मेदारी है.
>
> -पुष्कर सिंह धामी, सीएम, उत्तराखंड